

No. CD-11012/01/2020-Coord.  
Government of India  
Ministry of Road Transport & Highways  
(Coordination Section)  
Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi - 110001

---

Dated the 10<sup>th</sup> December, 2021

**OFFICE MEMORANDUM**

Subject: - Monthly Summary for the Cabinet for the Month of November, 2021.

A copy of the unclassified portion of the Monthly Summary (Both English & Hindi) for the Cabinet pertaining to the Ministry of Road Transport and Highways for the month of November, 2021 is enclosed herewith for information.



(Rakesh Kumar)

Under Secretary to the Government of India  
011-23739028

Encl. As above

To,

1. All members of the Council of the Ministers
2. Deputy Chairman, NITI Aayog, Yojana Bhavan, New Delhi
3. All Members of NITI Aayog, Yojana Bhavan, New Delhi. (10 spare copies)
4. Cabinet Secretary , Rashtrapati Bhavanm New Delhi
5. All Secretaries to Government of India
6. Information Officer, PIB , Shastri Bhavan, New Delhi

## Ministry of Road Transport and Highways

**Subject: Monthly Summary for the Cabinet for the month of November, 2021.**

1. **Award and construction of National Highways:** The Ministry has constructed 5,118 K.M. of National Highways up to November in 2021-22 as compared to 6,207 K.M. up to November in 2020-21. The award figure is 5,578 K.M. during this period as compared to 6,764 K.M. in the previous year.
2. **Major changes in the MCA of TOT Model:** The Ministry has approved major changes in the Model Concession Agreement (MCA) of Toll Operate Transfer (TOT) subsequent to the concurrence of Inter- Ministerial Committee. Changes in the MCA of TOT allowing NHAI to undertake capacity augmentation in a particular section of the Project Highway and small improvement works have been made. Further, in case the concessionaire faces revenue loss due to capacity augmentation undertaken by NHAI, the same will be reimbursed to the concessionaire by the Authority in order to ensure proper valuation of ToT projects. Similarly, it has also been decided that in case of any increase or decrease in tollable length due to capacity augmentation, the concessionaire will either pay the money or receive the compensation so that the concessionaire enjoys a financial situation as if no such Capacity Augmentation had taken place.
3. **Modifications in the RFP documents:** The Ministry has approved modifications in the Request for Proposal (RFP) documents for engaging the consultancy works i.e. DPR, Authority Engineer (AE), Independent Engineer (IE) to make bidding documents compliant with Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017 and Rule 144(xi) of GFR.
4. **Extension in the date of applicability of CEV(IV) Emission Norms:** This Ministry, vide GSR 598(E) dated 30th September, 2020, had amended CMVR, 1989 to separate the emission norms for Agricultural machinery and Construction Equipment Vehicles (CEV) and notified that implementation of CEV-IV emission norms will come in to force from 1st April, 2021. It has also been provided that the vehicles manufactured with CEV-III norms shall be registered within six months from the date of manufacture. Ministry vide GSR 800(E) dated 15th November, 2021 has now decided to extend the period of registration by two months , i.e up to 30th Nov 2021.
5. **Loutolim to Verna Inaugurated in Goa:** Hon'ble Minister of Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari inaugurated a four lane section from Loutolim village to Industrial Development Corporation, Verna on NH-566 at Verna, Goa on November 1,

2021. The 3.84 kms stretch of road is the missing link road which is constructed at the estimated cost of Rs. 184.05 crores. Total length of the project is 7.32 km, and starts from Loutolim to Titan Gate of Verna Industrial Corporation. The travel distance from Ponda to Mormugao is reduced by 12kms, thus reducing travel time by 30 minutes.

6. **Four laning of key sections of Shri Sant Dnyaneshawar Maharaj Palkhi Marg and Shri Sant Tukaram Maharaj Palkhi Marg:** Hon'ble Prime Minister laid the foundation stone for four laning of five sections of Shri Sant Dnyaneshawar Maharaj Palkhi Marg (NH-965) and three sections of Shri Sant Tukaram Maharaj Palkhi Marg (NH-965G) at Pandharpur in Maharashtra on 08.11.2021. This will facilitate the movement of Lord Vitthal's devotees coming from all over the nation and beyond to Pandharpur. Hon'ble PM also dedicated to the nation and laid foundation stone for 13 highway projects of total length 574 km with an estimated cost of Rs 12,294 crore. Hon'ble Minister of Road Transport and Highways was also present on the occasion.
7. **Setting up of Vehicle Scrapping and Recycling Facility:** Hon'ble Minister for Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari inaugurated the Vehicle Scrapping and Recycling Facility set up by Maruti Suzuki Toyotsu India Private Limited (MSTI) at Noida on 23.11.2021. Hon'ble Minister said that the policy aims at creating an ecosystem for phasing out unfit and polluting vehicles from the Indian roads and to meet this objective state-of-the-art scrapping and recycling units are needed and will help in increasing automobile sales, provide employment, reduce import cost, generate incremental GST revenue and help to solve the global shortage of semi - conductor chip. He further stated that the policy provides an important link in creating circular economy (waste to wealth) for the country.
8. **Standing Finance Committee (SFC) meetings:** In the month of November, 2021, a total 18 nos. of projects were considered by the Standing Finance Committee. The 18 projects of length 732.394 Km and total capital cost of Rs. 16,235.23 Cr. were appraised by SFC and recommended for approval.

\*\*\*\*\*

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

विषय: मंत्रिमंडल के लिए नवंबर , 2021 माह का मासिक सारांश।

- 1. राष्ट्रीय राजमार्गों को सौंपना और निर्माण :** मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 में नवंबर तक 6,207 किलोमीटर की तुलना में वर्ष 2021-2022 में नवंबर तक 5,118 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है। इस अवधि के दौरान सौंपा गया आंकड़ा 5,578 किलोमीटर है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 6,764 किमी था।
- 2. टीओटी मॉडल के एमसीए में बड़े बदलाव:** मंत्रालय ने अंतर-मंत्रालयी समिति की सहमति के बाद टोल ऑपरेट ट्रांसफर (टीओटी) के मॉडल रियायत समझौते (एमसीए) में बड़े बदलावों को मंजूरी दी है। एनएचएआई को परियोजना राजमार्ग के एक विशेष खंड में क्षमता वृद्धि करने के लिए वाले टीओटी के एमसीए में परिवर्तन करने की स्वीकृति दी है और छोटे सुधार कार्य किए गए हैं। इसके अलावा, यदि एनएचएआई द्वारा किए गए क्षमता वृद्धि के कारण रियायतग्राही को राजस्व हानि का सामना करना पड़ता है, तो टीओटी परियोजनाओं का उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसी तरह, यह भी निर्णय लिया गया है कि क्षमता वृद्धि के कारण टोल योग्य लंबाई में किसी भी वृद्धि या कमी के मामले में, रियायतग्राही या तो पैसे का भुगतान करेगा या मुआवजा प्राप्त करेगा ताकि रियायतग्राही को वित्तीय स्थिति का लाभ मिले मानो कि ऐसी कोई क्षमता वृद्धि नहीं हुई थी।
- 3. आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन:** मंत्रालय ने परामर्श कार्यो अर्थात डीपीआर, प्राधिकरण अभियंता (एई), स्वतंत्र अभियंता (आईई) को शामिल करने के लिए अनुरोध हेतु प्रस्ताव में संशोधनों को स्वीकृति प्रदान करती है ताकि बोली लगाने वाले दस्तावेजों को लोक अधिप्राप्ति( मेक इन इंडिया को प्रथमिकता देते हुए) आदेश, 2017 और साकानि के नियम 144(xi) के अनुरूप बनाया जा सके।
- 4. सीईवी (IV) उत्सर्जन मानदंडों की अनुप्रयोज्यता की तारीख में विस्तार:** इस मंत्रालय ने साकानि 598 (अ) दिनांक 30 सितंबर, 2020 के माध्यम से कृषि मशीनरी और निर्माण उपस्कर वाहनों (सीईवी) के लिए उत्सर्जन मानदंडों को अलग करने के लिए सीएमवीआर, 1989 में संशोधन किया था और यह अधिसूचित किया गया है कि सीईवी-IV उत्सर्जन मानदंडों का कार्यान्वयन 1 अप्रैल, 2021 से लागू होगा। यह भी प्रावधान किया गया है कि सीईवी-III मानदंडों के साथ निर्मित वाहनों को निर्माण की तारीख से छह महीने के भीतर पंजीकृत किया जाएगा। मंत्रालय ने सा.का.नि 800 (अ) दिनांक 15 नवंबर, 2021 के माध्यम से अब पंजीकरण की अवधि को दो महीने यानी 30 नवंबर 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया है।

5. **गोवा में लुटोलिम से वेरना का उद्घाटन:** माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने 1 नवंबर, 2021 को, गोवा के वेरना में रारा-566 वेरना पर, लुटोलिम गांव से औद्योगिक विकास निगम तक चार लेन खंड का उद्घाटन किया। सड़क का 3.84 किलोमीटर खंड मिसिंग लिंक रोड है जिसका निर्माण 184.05 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया गया है। परियोजना की कुल लंबाई 7.32 किमी है और लुटोलिम से वेरना औद्योगिक निगम के टाइटेन गेट से शुरू होती है। पोंडा से मोरमुगाओ की यात्रा दूरी 12 किमी कम हो जाती है, इस प्रकार यात्रा के समय में 30 मिनट की कमी आती है
6. **श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग और श्री संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग के प्रमुख खंडों को चार लेन का बनाना** माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 08.11.2021 को महाराष्ट्र के पंढरपुर में श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग (रारा-965) के पांच खंडों और श्री संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग (रारा-965जी) के तीन खंडों को चार लेन का बनाने का शिलान्यास किया । इससे देश भर से और विदेशों से पंढरपुर आने वाले भगवान विठ्ठल के भक्तों के आने-जाने में आसानी होगी। माननीय प्रधान मंत्री ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया है और 12,294 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की 574 किलोमीटर कुल लंबाई की 13 राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी है । इस अवसर पर माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भी उपस्थित थे।
7. **वाहन स्क्रेपिंग और रीसाइक्लिंग सुविधा की स्थापना:** माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने 23.11.2021 को नोएडा में मारुति सुजुकी टॉयत्सु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एमएसटीआई) द्वारा स्थापित वाहन स्क्रेपिंग और रीसाइक्लिंग सुविधा का उद्घाटन किया। माननीय मंत्री ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य भारतीय सड़कों से अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक स्क्रेपिंग और रीसाइक्लिंग इकाइयों की आवश्यकता है और इससे ऑटोमोबाइल बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी, रोजगार मिलेगा, आयात लागत कम होगी, जीएसटी राजस्व बढ़ेगा और सेमी-कंडक्टर चिप की वैश्विक कमी को हल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि यह नीति देश के लिए सर्कुलर इकोनॉमी (अपशिष्ट से धन) बनाने में एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रदान करती है।
8. **स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठकें:** स्थायी वित्त समिति द्वारा नवंबर, 2021 माह में कुल 18 परियोजनाओं पर विचार किया गया। स्थायी वित्त समिति द्वारा 732.394 किलोमीटर लंबाई वाली और कुल 16,235 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत की 18 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया और इसकी अनुमोदन के लिए सिफारिश की गई।

\*\*\*\*\*